scientific source finding, construction of water harvesting structures for recharge, extenslion of distribution systems of existing schemes to needy areas, etc. are being implemented to mitigate drinking water shortage.

(c) No Sir, such a proposal was considered earlier by Gujarat State Government and not found techno-economically viable.

(d) In line with the objective of the International Decade on Water Supply and Sanitation, it is aimed to supply the entire rural population with safe and adequate drinking water by the end of the Seventh Plan period. The total irrigation potential of the country is 113 million hectares. About 60 per cent of this potential has already been created. The Seventh Plan envisages creation of additional irrigation potential of about 12.9 million hectares. It lis expected that the ultimate irrigation potential of the country would be fully created by about 2010 A.D.

Siphoning off of lakhs of rupees in NEMC hot mix plant

1416. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that siphoning off of lakhs of Rupees by the senior officials of Civil Engineering Department was unearthed in NDMC hot mix plant; and

(b) what is the total amount misappropriated and the names of the officers involved in scandal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) No, Sir. However, the Administrator, New. Delhi Municipal Committee has appointed a High Power Committee to look into the lapses pointed out by the Chief Technical Examiner's Organisation of the Central Vigilance Commission about the improper functioning of the NDMC Hot Mix Plant.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार

1417. **श्री राधाकिशन मालवीय :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर किए गए अत्याचारों के संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए ; और

(ख) दर्ज किए गए इन मामलों में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) दो विवरण, विवरण-I अनुसूचित जातियों के लिए तथा विवरण-II अनुसूचित जनजातियों के लिए संलग्न है (नीचे देखिये)

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के संबंध में राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को एहतियाती, निवारक, दंडात्मक और पुनर्वासात्मक उपायों का सुझाव देते हुए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिन राज्यों में अत्याचारों की बढ़ती प्रवृत्ति है कल्याण मंत्री ने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है ।

विवरण–I

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1985 और 1986 के दौरान अनुसूचित जातियों पर अन्य लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों से संबंधित दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अत्याचार से संबंधित मामलों की कुल संख्या	
		1985	1986
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	166	193
2	असम	शून्य	15
3	बिहार	1452	1633
4	गुजरात	750	649
5	हरियाणा	121	82
6	हिमाचल प्रदेश	49	50
7	जम्मू और कश्मीर	53	89
8	कर्नाटक	294	182
9	केरल	300	476
10	मध्य प्रदेश	5133	4421
11	महाराष्ट्र	428	462
12	उड़ीसा	159	183
13	पंजाब	32	19
14	राजस्थान	1437	1481
15	तमिलनाडु	852	758
16	उत्तर प्रदेश	4135	4697
17	पश्चिम बंगाल	11	9
18	दिल्ली	1	शून्य
19	पांडिचेरी	शून्य	4
	कुल	15373	15403

नोट : अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की जानकारी शून्य है।

विवरण–II

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1985 और 1986 के दौरान अनुसूचित जनजातियों पर अन्य लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों से संबंधित दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अत्याचार से संबंधित दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या	
		1985	1986
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	22	43
2	असम	23	19
3	बिहार	221	154
4	गुजरात	125	171
5	कर्नाटक	1	शून्य
6	केरल	80	85
7	मध्य प्रदेश	2955	2721
8	महाराष्ट्र	169	221
9	मणिपुर	2	17
10	नागालैन्ड	शून्य	4
11	उड़ीसा	46	52
12	राजस्थान	379	420
13	तमिलनाडु	1	3
14	उत्तर प्रदेश	4	शून्य
15	पश्चिम बंगाल	16	16
16	अरुणाचल प्रदेश	11	10
17	दादर और नगर हवेली	शून्य	3
18	मिजोरम	शून्य	6
	कुल	4055	3945

नोट : अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की जानकारी शून्य है।